लिए सतर्क हैं। किए गए विशेष उपायों में विशिष्ट आसूचना एकत्र करना, पत्तनों और विमानपत्तनों पर रंगीन असबाब एक्स-रे मशीनें लगाना और पात्र यात्रियों को दस कि.ग्रा. सोने के आयात की अनुमति देकर सोने के आयातों को और अधिक उदार बनाना शामिल है।

Revenue collected/Budgeted for 1995-96

691. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of revenue collected during 1995-96 and the budgeted estimates for the same period; and

(b) if there was any deficit between the revenue collected and the revenue estimated during 1995-96, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Budget estimates and amount of revenue collected from major Central Taxes during 1995-96 were as under:—

(Rs. in crores)

Name of the tax	Revised Budget Estimates	Collection
1. Customs	35352	35502
2. Union Excise	41000	40784
3. Corporation tax	16000	16487
4. Income-tax	15100	15587

(b) Does not arise.

Disparity in Tax Rates among States

692. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the growing disparity in tax rates among States;

(b) if so, the steps taken by Government to remove this disparity; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A meeting of the Finance Minister of all States and Union Territories was convened by the Union Finance Minister on 4th July, 1997 to discuss the Report of the Group of Officials and Experts on Taxation of Inter-State Sales and the Report of Committee of State Finance Ministers on Stamp Duty Reforms. There was general consensus on the imperatives of reforming the Central Sales Tax and Stamp Duty and introduction of VAT.

Nationalised Banks involved in CRB Scam

693. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJI-RAO SHINDE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) which nationalised banks have been found to have fallen prey to the CRB Scam;

(b) to what extent, indicating the amount of money swindled from each bank and the mode adopted by CRB and bank management for the purpose; and

(c) what steps have since been taken to recover the money?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) CRB Capital Markets Ltd. (CRBCML) was granted a facility, by the Mumbai Main Branch of State Bank of India, of encashment at par, of warrants issued by the company in repayment of fixed deposits, interest payable thereon and brokerage warrants at all branches of State Bank of India. The company had agreed, *inter-alia*, to prefund the relative accounts ensuring that the accounts have sufficient balance when the warrants were presented for payment. However, the company fraudulently overdrew the account by an amount of over Rs. 58 crores (provisional). The company has also overdrawn its interest warrant account and brokerage warrant account with the Capital Markets Division, Mumbai Main Office of Bank of Baroda by about Rs. 1.90 crores (provisional). The company also enjoyed credit

facilities from some public sector banks and the exposure of these banks is presently estimated to be in the region of Rs. 12 crores.

(c) Consequent upon a petition filed by the Reserve Bank of India under section 45 MC of the Reserve Bank of India Act, the Delhi High Court has appointed a Provisional Official Liquidator. The Liquidator has initiated steps to crystallize the assets and liabilities of the company. He is being assisted by the officials of RBI, CBI and some public sector banks in this regard. The issue of settlement of claims of creditors, including banks, is now subjudice and would proceed as per the provisions of law and the directions of the Delhi High Court.

प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी निर्देश

694. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या सरकार देश में बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किए जाने के पुराने निर्देशों में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो दिये गये नवीन निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए लक्ष्य में निवल बैंक ऋण के 33 1/3 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। और यह मार्च, 1985 तक प्राप्त किया जाना था। तब से ही निर्धारित लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राथमिकता क्षेत्र को निदेशित ऋण देने का मूल्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खण्ड के अन्तर्गत कमजोर वर्गों और छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करना है और इसीलिए बैंकों से कहा गया है कि वे इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की अनुपालना करें। तथापि, निवेश आदि के मूल्य में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

(i) लघु उद्योगों की परिभाषा में समय-समय पर संशोधन किया गया है और वर्तमान में इसमें वे ईकाइयां सम्मिलित हैं जिनकी संयंत्र और मशीन में निवेशों की मूल लागत 60 लाख रुपए (अनुषंगी और निर्यातोन्मुख ईकाइयों के लिए 75 लाख रुपए) से अधिक नहीं है।

(ii) प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत निजी खुदरा व्यापारियों (उनके अलावा जो अनिवार्य वस्तु वस्तुओं, उचित दर की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी स्टोर से संबंधित हैं) को अग्रिमों के लिए सीमा मार्च, 1994 में 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दी है।

(iii) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत छोटे कारोबार की परिभाषा की मार्च, 1994 मे पुनरीक्षा की गई है जिसमें कि उन ईकाइयों (जो मुख्यत: व्यावसायिक सेवा से भिन्न कोई अन्य सेवा प्रदान कराने के प्रयोजन से स्थापित की गई हों) को सम्मिलित किया जा सके तथा जिनकी कारोबार के प्रयोजन के लिए मूल प्रयोग किए गए उपस्कर की लागत 10 लाख रुपए से अधिक न हो और जिसकी कार्यशील पूंजी की सीमा 5 लाख रुपए तक हो (जो क्रमश: 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए से संशोधित की गई है)

(iv) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्तियों को अग्रिमों के लिए सीमा मई, 1994 में (2 लाख रुपए से) 5 लाख रुपए तक बढाई गई है जिसमें से 1 लाख रुपए से अधिक कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यसवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चिकित्सकों जो अपनी प्रेक्टिस अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, के लिए तदनुरूपी सीमा क्रमश: 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है।

(v) प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, आवास वित्त के लिए सीमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त, दोनों के संबंध में फरवरी, 1997 में प्रति आवास ईकाई 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है।

विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक सहायता

695. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा भारत को वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न रूपों में